भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1285

08.12.2025 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक

1285. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डीः
श्री के. ई. प्रकाशः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत 2026 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई) में 13 स्थान से गिरकर 23वें स्थान पर आ गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार ने इन चिंताओं के समाधान के लिए कोई अंतरिम लक्ष्य तय करने अथवा नयी योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को अद्यतन जलवायु लक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जिसमें जीवाश्म ईंधन के उपयोग से दूर जाने तथा ऊर्जा दक्षता के उपयोग में सुधार लाने की दिशा में सरकार की स्वैच्छिक कार्रवाइयों का उल्लेख है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा ऐसा ब्यौरा कब तक प्रस्तुत किया जाएगा?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई), 2026 में भारत की स्थिति, सीसीपीआई का प्रकाशन करने वाली स्वतंत्र एजेंसी जर्मनवॉच ने 23वां स्थान बताया है। वार्षिक सीसीपीआई रैंकिंग में भिन्नताएँ उनकी अपनी कार्यप्रणाली और ऐसे मानदंडों को दिए गए भार पर आधारित होती हैं जैसे कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की प्रवृत्ति, नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा, ऊर्जा उपयोग की प्रवृत्तियाँ, और जलवायु नीति का मूल्यांकन।

हालांकि, सरकार किसी भी बाहरी रैंकिंग को घरेलू नीति निर्माण के लिए आधार के रूप में मान्यता नहीं देती है, क्योंकि भारत की जलवायु कार्रवाई राष्ट्रीय रूप से निर्धारित प्राथमिकताओं और विकासात्मक आवश्यकताओं द्वारा निर्देशित होती है। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के तीव्र विस्तार, जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में कमी, ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, और ई-मोबिलिटी, हरित हाइड्रोजन और संधारणीय जीवनशैली को प्रोत्साहित करने सहित कई उपाय किए हैं।

(ख) से (घ) सरकार ने जलवायु संबंधी सरोकारों का समाधान करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय मिशनों और योजनाओं के तहत पहले ही कई प्रगतिशील उपायों की घोषणा कर दी है। इनमें शामिल हैं:

- राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का कार्यान्वयन,

- पीएटी (परफॉर्म, अचीव और ट्रेड) और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के तहत प्रमुख क्षेत्रों के लिए चरणबद्ध परिवर्तन योजनाओं की अधिसूचना,
- राष्ट्रीय सौर मिशन और राष्ट्रीय पवन ऊर्जा मिशन का जारी कार्यान्वयन,
- राज्य-स्तरीय जलवायु कार्रवाई योजनाएं, और
- संधारणीय उपभोग को बढ़ावा देने के लिए लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) के तहत पहलें।

ये कार्य मध्यवर्ती पड़ाव के रूप में हैं जो भारत के राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हैं।

भारत ने पहले ही अपनी अद्यतन एनडीसी जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेन्शन (यूएनएफसीसी) को प्रस्तुत कर दिया है। अद्यतन एनडीसी में निम्न-कार्बन मार्ग की ओर परिवर्तन के लिए स्वैच्छिक कदम शामिल हैं, जिनमें गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाना और सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को कम करना शामिल है।

अद्यतित एनडीसी में निम्नलिखित मुख्य तत्व शामिल हैं:

- 2005 के स्तर से 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी,
- 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करना,
- लाइफ पहल के तहत जलवायु-अनुकूल जीवनशैली को बढ़ावा देना।

भारत ने वर्ष 2005 और वर्ष 2020 के बीच सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी हासिल की है, और अपनी स्थापित विद्युत क्षमता का 50% से अधिक हिस्सा गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से तय समय से बहुत पहले प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान मूल्यांकन (आईएसएफआर 2023) दर्शाता है कि भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 समतुल्य तक पहुँच गया है; जो यह दर्शाता है कि आधार वर्ष 2005 की तुलना में, भारत ने पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक प्राप्त कर लिया है, जबकि वर्ष 2030 तक लक्ष्य 2.5 से 3.0 बिलियन टन है। इसके अलावा, भारत ने नवंबर, 2022 में अपने दीर्घकालिक निम्न-कार्बन विकास कार्यनीतियों (एलटी-एलईडीएस) को यूएनएफसीसीसी को प्रस्तुत किया, जो वर्ष 2070 तक निवल शून्य पाने के लक्ष्य की पुष्टि करता है।

इसके अलावा, भारत नवीकरणीय ऊर्जा के वितरण का विस्तार करता रहा है, हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देता है, और अपने दीर्घकालिक 'जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा कार्यनीति' के हिस्से के रूप में बड़े पैमाने पर ऊर्जा-कुशलता उपाय लागू करता है।

*****